# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14648/2023

महेंद्र दान पुत्र श्री रानी दान, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट पटाऊ कल्लन, तहसील पंचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके सचिव, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सीएस कोटवानी और श्री कनिष्क सिंघवी।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री राजेश पुनिया।
श्री दीपक चांडक, एजीसी।

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश(मौखिक)**

**15/03/2024**

1. यहां याचिकाकर्ता, भारतीय सेना का एक पूर्व सैनिक, सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति का आकांक्षी है। हालांकि, प्रतिवादी-राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है। उन्हें आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भविष्य की भर्तियों में भाग लेने के लिए दिनांक 01.09.2023 (अनुलग्नक 20) के आदेश द्वारा भी रोक दिया गया है। वह प्रतिवादियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने

की अनुमति देने के निर्देश के साथ-साथ यहां आरोपित आदेश को रद्द करने की मांग करता है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा दलील दी गई प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि:

2.1 प्रतिवादियों ने सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 03.02.2021 (अनुलग्नक 1) का विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया और उसे प्रवेश पत्र (अनुलग्नक 6) जारी किया गया और वह लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ। इसके बाद, याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 494/202 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता ने जमानत पर रिहा होने के बाद, आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधित्व दायर करने के माध्यम से प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर, आरपीएससी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

2.2. दिनांक 01.06.2022 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2285/2023 के रूप में एक रिट याचिका पेश की। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2023 के आदेश (अनुलग्नक 15) द्वारा इसका निपटारा किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 27.04.2023 (अनुलग्नक 16) प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 29.05.2023 (अनुलग्नक 17) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उसी का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता ने फिर से एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7274/2023 के तहत एक रिट याचिका पेश की, जो विचाराधीन है। इस बीच, आरपीएससी ने दिनांक 01.09.2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को आरपीएससी द्वारा भविष्य में की जाने वाली किसी भी चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने से रोक दिया। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

4. सबसे पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन एफआईआर से उत्पन्न आरोप-पत्र 09.12.2021 को बहुत पहले दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

5. उन्होंने कहा कि उक्त आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि जांच करने के बाद वह निर्दोष है।

6. तदनुसार, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने बताया कि अनुलग्नक-आर/2 के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता का विशेष रूप से नाम लिया गया है।

7. जैसा भी हो, इस स्तर पर, जब याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में नामित भी नहीं किया गया है, तो उसे राज्य एजेंसियों द्वारा की जाने वाली किसी भी चयन प्रक्रिया में शामिल होने से हमेशा के लिए रोकना बहुत कठोर सजा होगी। मेरा विचार है कि संबंधित एफआईआर से उत्पन्न मुकदमे के परिणाम के आधार पर, याचिकाकर्ता को बाद में इसके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

8. अदालत के प्रश्न पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट (अनुलग्नक आर/2) एक आरोप-पत्र नहीं है और केवल आई.ओ. की राय है। उन्होंने उचित रूप से कहा कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे के परिणाम के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

9. उपर्युक्त आधार पर, इस रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि वह प्रतिवादी-राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के समक्ष एक उचित आवेदन दायर कर भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान परीक्षा में भाग लेने की पूर्व अनुमति मांग सकता है। विवादित आदेश उस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।